



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2017/फाल्गुन 30, 1938

No. 103]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2017/PHALGUNA 30, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 23 फरवरी, 2017

**सं टीएमपी/55/2016-PPT.**— महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र(आईओएचपी) पर लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन के लिए उप-श्रमकर लगाने के बारे में पारादीप पत्तन न्यास(पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं टीएमपी/55/2016-PPT

पारादीप पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(फरवरी 2017 के 8 वें दिन पारित)

यह मामला, लौह अयस्क प्रहस्तक संयंत्र(आईओएचपी) पर लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन के लिए श्रम उपकर लगाने के बारे में पारादीप पत्तन न्यास(पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. मार्च, 2011 में अनुमोदित दरमानों में पीपीटी के वर्तमान दरमान (एसओआर) में खंड 2.1 में क्रम सं. (5)आईओएचपी के माध्यम से लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन के लिए, वर्तमान दरमान इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	सामान का विवरण		दर प्रति मी टन या उसका कोई भाग (रु.)	
			विदेशी	तटीय
4.	(क)	लौह अयस्क (आईओएचपी के माध्यम से)		
		(i) 1.0 एमटीपीए तक	23.45	23.45
		(ii) 1.0 एमटीपीए और 1.5 एमटीपीए के मध्य पोत पर प्रहस्तन कार्य	20.05	20.05

	(iii) पोत पर 1.5 एमटीपीए से अधिक प्रहस्तन कार्य	16.65	16.65
(ख)	टिप्पलिंग प्रभार	20.40	20.40
(ग)	लौह अयस्क (मानव द्वारा प्रहस्तन)	23.45	23.45

2.2. तथापि, पीपीटी के वर्तमान दरमानों में आईओएचपी के माध्यम से लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन के लिए दरों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः पीपीटी ने इस संदर्भ में प्रस्ताव किया है।

3.1. पीपीटी के 08 सितंबर, 2016 के प्रस्ताव में उल्लेखित मुख्य बिंदुओं का सारांश इस प्रकार है:

- (i) दो टिप्पलर्स वाली लौह अयस्क बर्थ पीपीटी की सबसे पुरानी बर्थ है जो वर्ष 1966 में प्रथमतया वैगनों से लौह अयस्क की मशीनी ढंग से टिप्पलिंग और बर्थ पर पोतीय लोडरों द्वारा लौह अयस्क के मशीनी ढंग से लदान करने के लिए लगायी गई थी। वर्षों के दौरान बर्थ पर यह यंत्रीकृत प्रणाली समय-समय पर पूंजीगत निवेश करके आधुनिक बना दी गई है।
- (ii) केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों के कारण वर्ष 2012-13 में लौह अयस्क से संबंधित कार्गो का पोत पर प्रहस्तन कार्य रोक दिया गया था जिसे चीन से उठने वाली मांग से जोड़ा गया। पीपीटी ने इस सुविधा को आईओएचपी के माध्यम से टीएनजीईडीसीओ तथा एनटीईसीएल के तापीय कोयला के मशीनी ढंग से लदान के लिए बीओएक्सएन(खुले वैगन) से तापीय कोयला की टिप्पलिंग के लिए प्रयोग किया।
- (iii) सफाई, प्रेषण, और बीओएक्सएन कोयला रेकों से उतरायी कार्य पर लगाए जाने वाले सीएफएंडएच के प्रहस्तन कामगारों की औसतन नियुक्ति बहुत अधिक कम हो गई थी। यह तापीय कोयला मशीनी कोयला प्रहस्तन संयंत्र (एमसीएचपी) भंडारण क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था और मशीनों द्वारा ही लादा जा रहा था। परिणामतः सीएफएंडएच कामगारों द्वारा सृजित समस्या के समाधान के कारण 14 नवंबर 2014 से आईओएचपी पर टिप्पलर बेकार हो गए थे।
- (iv) पीपीटीके न्यासी बोर्ड द्वारा (सीएफएंडएच कामगार प्रबंधन के निर्णयानुसार) सीएफएंड एंड कामगारों की समस्या/ औद्योगिक विवाद को निपटाने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के साथ सीएफएंडएच कामगारों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के निधियन के लिए पीपीटी द्वारा वित्तीय अनुदान में बढोत्तरी करने पर विचार किया गया था जिससे आईओएचपी टिप्पलर के माध्यम से तापीय कोयला के मशीन द्वारा प्रहस्तन करने का रास्ता खुल सकेगा। आईपीए के माध्यम से पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त परामर्शदाता- बीसीजी ने इस लाभ के बारे में कि इससे आईओपी से 3.5 लाख मीट्रिक अतिरिक्त कोयले का निर्यात हेतु प्रहस्तन हो सकेगा और पीपीटी के अन्य मानकों के अलावा तापीय कोयला निर्यातकों के लिए लाभकारी होगा, इस लिए पीपीटी को और जांच पड़ताल करने का अनुरोध किया था।
- (v) पीपीटी बोर्ड द्वारा संगठित उप न्यासी समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न मुद्दों पर केंद्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई:
  - (क) 320 कामगारों को वीआरएस प्रदान करने के लिए अनुदान के रूप में रु. 49 करोड़ रुपये की राशि पीपीटी द्वारा प्रदान करना/2 रोक मानवों द्वारा तथा दो रोक मशीनों द्वारा(टिप्पलों काध्यम से) प्रहस्तन के लिए प्रस्तावित अनुदान का पूरा किया जा सकता है। वीआरएस के लिए व्यय की जाने वाली रु. 49 करोड़ की राशि को दो वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।
  - (ख) शेष 740 कामगारों के बृहत रूप से वीआरएस को खुला रखने की अनुमति देना जिसके लिए कुल 127 करोड़ रुपये की अनुदान राशि पीपीटी द्वारा प्रदान की जाए। इस राशि की प्रतिपूर्ति, 4 बीओएक्सएन तापीय कोयला रोक प्रतिदिन मशीनों द्वारा उतारने से की जा सकती है। ताकि कुल रु. 127 करोड़ की अनुदान राशि को अगले 2.1/2 वर्ष में पूरा किया जा सके।
  - (ग) विचार किया गया और सहमति बनी कि क्योंकि पीपीटी की वर्तमान स्थिति और सरकारी नीति में ऐसा कोई विनियम नहीं है, इसलिए समग्र स्थिति का उल्लेख पोत परिवहन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए कि पत्तन

के साथ सीएफ एंड एच कामगारों के पत्तन के उन्नयन में दशकों लंबे समय तक साथ देने के कारण उनके लिए सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए।

- (घ) कामगारों तथा सीएफएंड एच कामगारों की यूनियन से प्राप्त अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में विचार कर कामगारों के नियमितिकरण के मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था ताकि पीपीटी पर कार्यपरक शांति और मेलजोल बना रहे।
- (vi) पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 22 मार्च, 2016 के अपने पत्र सं. एलबी-1601/5/2013-डीओ(एल) के द्वारा अपनी अनापत्ति व्यक्त की। प्रबंधन समिति द्वारा विशेष सर्वेयरेंस पैकेज (एसएसपी) जिसे वीआरएस का नाम दिया गया, को प्रबंधन समिति को निधि जारी करने की अनुमति प्रदान की। पोत परिवहन मंत्रालय ने पीपीटी को यह परामर्श दिया कि वह यह सुनिश्चित भी करले कि आईओएचपी के माध्यम से प्रहस्तन किए जाने वाले कोयले पर श्रम उपकर लगाकर यह अनुदान पूरा कर लिया जाएगा।  
[संदर्भाधीन पोत मंत्रालय का पत्र सं. एलबी-1601/5/2013 डीओ(एल) दिनांक 22 मार्च, 2016 आईओएचपी के द्वारा तापीय कोयला के प्रहस्तन पर उप-श्रम-कर लगान के 24 मई, 2016 के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है।]
- (vii) पीपीटी ने रु. 77,81,19,663,रु. की अनुदान राशि प्रबंधन समिति को पहले ही सौंप दी है जो इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	अनुदान देने की तिथि	एसएसपी के अधीन सीएफ एंड एच कामगारों की संख्या	पीपीटी द्वारा प्रदान की गई राशि (रु.)
1	05.05.2016	283	43,64,03,213/-
2	31.05.2016	188	34,17,16,450/-
	<b>योग</b>	<b>471</b>	<b>77,81,19,663/-</b>

आगे सीएफएंड एच कामगारों के लिए पूर्ववर्ती किए गए निर्णय के अनुसार एसएसपी दिनांक 22.03.2016 से 21.03.2017 तक खुली है। पीपीटी पोत परिवहन मंत्रालय की अनुमति के अनुसार आगे सीएफएंड एच कामगारों के शेष एसएसपी के लिए रु.981830337 की अनुदान राशि खकुल लगभग 176 करोड़ में से) प्रदान करेगा।

- (viii). यह कुल व्यय राशि रु.130 प्रतिटन की दर से प्रस्तावित उप श्रम कर लगाकर पीपीटी द्वारा वसूल की जा सकती है। इस पर पीपीटी, एनजीईडीसीओ और एनटीईसीएल द्वारा तापीय कोयला के लिए रु. 120/- प्रति टन की दर से सहमति बनी है जिसे प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21 जून 2016 के आदेश सं0 टीएएमपी/31/2016 -पीपीटी के द्वारा तदर्थ आधार पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
- (ix). तदनन्तर, पीपीटी ने अनुभव किया कि संयंत्र की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग प्राथमिक तौर पर बेकार पड़ी आईओएचपी प्रणाली के प्रतिमाह लौह अयस्क पल्लों के लगभग 3.5 लाख टन के कार्गो प्रहस्तन हेतु इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है जो प्रहस्तन हेतु पड़ोसी पत्तनों में जा रहे थे और वे भी। पीपीटी की ये पार्टियां, लौह अयस्क पल्लों के टिप्पलर द्वारा मशीनी प्रहस्तन से तापीय कोयला के समान प्रहस्तन के लिए तैयार हैं।
- (x). यह माना जाता है कि ऐसे लौह अयस्क पल्ले, यदि लगाया जाने वाला उप-श्रमकर, निजि पत्तनों पर कुल लागत की तुलना में आईओएचपी द्वारा लौह अयस्क पल्लों की शिपमेंट के लिए समग्र व्यय से स्पर्धा में कम होता है तो पोत पीपीटी का रुख करने लगेंगे।

- (xi) इस मामले में किए गए विश्लेषण के अनुसार आईओएचपी द्वारा प्रहस्तित तापी कोयला के मामले में वर्ष 2014-15 में लौह पल्लों का निष्पादन पोतीय दिवस निष्पादन अर्थात् 14,913 मी. टन की तुलना में अभीष्टतम क्षमता लगभग 25,000 मी. टन होने की परिकल्पना की गई है।
- (xii) इसलिए यह मानते हुए कि लौह अयस्क पल्लों के पोतीय दिवस निष्पादन पर विचारकरते हुए और यदि पीपीटी के रेल से दूरी निजि पत्तनों की तुलना में लगभग 30 किलोमीटर से अधिक होने पर भी शिप्पर रु. 59/- प्रति टन रेल भाड़ा तथा और यदि 120/- प्रतिटन श्रम उपकर भी लगाया जाता है तो भुगतान करने के लिए तैयार होगा। इसलिए आईओएचपी के माध्यम से भी लौह अयस्क पल्लों पर श्रम उपकर @ रु.70/- लगाने पर विचार किया गया।
- (xiii) इस विचार के साथ पीपीटी ने तटीय/विदेशी निर्यात के लिए लौह अयस्क पाल्लों के प्रहस्तन कार्य के अवसर पाए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने लौह अयस्क सामग्री के वैगनों द्वारा संचलन पर, जो पहले आंतरिक और निर्यात प्रयोजनों के लिए लिया जा रहा था 'दोहरे भाड़ा ढांचे' को हटाने के रेलवे बोर्ड के निर्णय के साथ लौह अयस्क सामग्री पर कस्टम ड्यूटी को युक्तियुक्त बनाने का निर्णय लिया है। इससे आईओएचपी के माध्यम से मशीनी टिप्पलिंग के लिए लौह अयस्क का संचलन कार्य आरंभ हो गया है तथापि लौह अयस्क सामग्री पर कोई उप श्रमकर लगाने पर कोई विचार नहीं किया गया है क्योंकि आईओएचपी को प्रथमतया लौह अयस्क के प्रहस्तन हेतु तैयार किया गया था और प्राधिकरण द्वारा पीपीटी अनुमोदित दरमानों में किसी प्रकार के श्रम-उपकर पर कोई विचार नहीं किया गया था।
- (xiv) लौह अयस्क पल्लों के लिए प्रस्तावित श्रम उपकर रु. 70 प्रति मी. टन के लिए पीपीटी के न्यासी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।
- (पीपीटी के न्यासी बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की प्रति प्रस्तुत कर दी है जिसमें आईओएचपी पर लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन के लिए 70/- रुपये प्रति मी. टन का न्यासी बोर्ड के अनुमोदन का उल्लेख है)
- (xv) उपयोक्ता संगठन मै. जिंदल स्टील और पॉवर, लौह अयस्क पल्लों के टिप्पलिंग से लदान के लिए मशीनों द्वारा प्रहस्तन के लिए पत्तन के वर्तमान संविधिक प्रभारों के अतिरिक्त रु. 70/- प्रति मी. टन की दर से अतिरिक्त प्रभार (उपकर) देने पर सहमत हो गया है।
- (मै. जिंदल स्टील और पॉवर, के पत्र की प्रति पीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई है)

3.2. इस पारिप्रेक्ष्य में पीपीटी ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि तापीय कोयला के प्रहस्तन की भांति लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन के लिए रु 70/- प्रति मी. टन के प्रस्तावित उप श्रमकर का अनुमोदन किया जाए।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार पीपीटी के 8 सितंबर 2016 के प्रस्ताव से संबंधित उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए उनके पत्र दिनांक 16 सितंबर, 2016 के अंतर्गत भेज दिया गया था। किसी भी उपयोक्ता/उपयोक्ता संगठन ने मामले के तय होने तक अपनी अभ्युक्तियां नहीं भेजी हैं।

5. प्रस्ताव को स्वीकार करते समय पीपीटी को दिनांक 16 सितंबर 2016 के पत्र के माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि वह न्यासी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए एजेंडा नोट के अनुलग्नकों को भी प्रस्तुत करे। पीपीटी से यह अनुरोध भी किया गया था कि वह कुछ बिंदुओं पर मांगी गई सूचना/जानकारी आदि प्रस्तुत करे। 17 अक्टूबर 2016 तथा 16 नवंबर 2016 के स्मरण पत्रों के पश्चात पीपीटी ने 26 दिसंबर 2016 के ई मेल के अंतर्गत अपना प्रत्युत्तर दिया है। हमारे द्वारा मांगी गई जरूरी एवं सूचना आगे तालिकाबद्ध की गई है:

	प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी/स्पष्टीकरण	पीपीटी का प्रत्युत्तर
(क).	पीपीटी ने 8 सितंबर, 2016 के अपने प्रस्ताव में प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि सीएफएंडएच कामगारों के लिए वीआरएस के दायित्व की राशि की भरपाई के लिए आईओएचपी संयंत्र के माध्यम से लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन के लिए तदर्थ आधार पर रु. 70	भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार पीपीटी ने प्रबंधन समिति के कामगारों के लिए एसएसपी लागत, पीपीटी को वहन करनी होगी जो रु.176 करोड़ बनती है। इस राशि को पीपीटी का निवेश माना जाए जिसे व्याज सहित प्रस्तावित उप श्रम- कर के तौर पर वसूला जाएगा। यह मानते हुए कि (मई 2016 से नवंबर 2016 तक)

प्रति मी.टन की दर से उप श्रमकर की वसूली हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाए। इस संबंध में यह प्रासंगिक है कि प्रशुल्क नीति 2015 के अनुसार किसी भी कर का लगाया जाना निवेश पर प्रत्यागम घटक और प्रदान की गई सेवाओं के लिए होता है। इस परिप्रेक्ष्य में पीपीटी आईओएचपी के माध्यम से लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन की लागत वसूलने के लिए उप श्रमकर लगाने का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करें।

पिछले 7 माह के दौरान 1.5 मिलियन मी. टन कार्गो अर्थात् तापीय कोयला और लौह अयस्क पल्ले आईओएचपी पर प्रहस्तित किए जाएंगे। तदनुसार, रु. 110/- प्रति टन की दर से उप श्रमकर के हिसाब से आगामी 3 वर्ष के लिए परिकलन नीचे दिया जाता है।

#### प्रथम वर्ष

विवरण	राशि रु.
निवेश लागत (एसएसपी)	<b>176,00,00,000</b>
ब्याज (8%)	<b>14,08,00,000</b>
	<b>190,08,00,000</b>
उप श्रम-कर	<b>110</b>
मात्रा प्रति वर्ष (7 माह में 8.5 लाख टन मानते हुए)	<b>15,00, 0</b>
वसूल की जाने वाली वार्षिक राशि	<b>16,50,00,000</b>
टिप्पलिंग, आईओएचपी प्रभार, टर्मिनल प्रभार हार्लेज प्रभार @ 100 रु. प्रति टन की दर के कारण अप्रत्यक्ष निबल राजस्व	<b>15,00,00,000</b>
	<b>31,50,00,000</b>
आगामी वर्ष के लिए ले जाया गया	<b>158,58,00,000</b>

#### दूसरे वर्ष

विवरण	राशि रु.
निवेश लागत (एसएसपी)	<b>158,58,00,000</b>
ब्याज (8%)	<b>12,68,64,000</b>
	<b>171,26,64,000</b>
उप श्रम-कर	<b>110</b>
मात्रा प्रति वर्ष (7 माह में 8.5 लाख टन मानते हुए)	<b>15,00,000</b>
वसूल की जाने वाली वार्षिक राशि	<b>16,50,00,000</b>
टिप्पलिंग, आईओएचपी प्रभार, टर्मिनल प्रभार हार्लेज प्रभार @ 100 रु. प्रति टन की दर के कारण अप्रत्यक्ष निबल राजस्व	<b>15,00,00,000</b>
	<b>31,50,00,000</b>
आगामी वर्ष के लिए ले जाया गया	<b>139,76,64,000</b>

#### तीसरे वर्ष

विवरण	राशि रु.
निवेश लागत (एसएसपी)	<b>139,76,64,000</b>
ब्याज (8%)	<b>11,18,13,120</b>
	<b>150,94,7 ,1 0</b>

		उप श्रम-कर	110
		मात्रा प्रति वर्ष (7 माह में 8.5 लाख टन मानते हुए)	15,00,000
		वसूल की जाने वाली वार्षिक राशि	16,50,00,000
		टिप्पलिंगए आईओएचपी प्रभार, टर्मिनल प्रभार हार्लेज प्रभार @ 100 रु. प्रति टन की दर के कारण अप्रत्यक्ष निबल राजस्व	15,00,00,000
			31,50,00,000
		आगामी वर्ष के लिए ले जाया गया	119,44,77,120
(ख).	पीपीटी,आईओएचपी पर प्रहस्तन किए जाने वाले लौह अयस्क पल्लों की वार्षि मात्रा सूचित करे।	ऊपर बिंदु (क) पर पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है।	
(ग).	पीपीटी ने लौह अयस्क पल्लोंके लगभग 25000 मी. टन कार्गो का पोत दिवस में निष्पादन पर विचार करते हुए 70/- प्रति मी. टन की दर से लौह अयस्क पल्लों पर उप श्रम कर का प्रस्ताव किया है तथा यह तथ्य कि पीपीटी रेलवे दूरी निजी पत्तनों से लगभग 30 कि. मी. से अधिक है। इस संबंध में 70/- रु. प्रति कि.मी. के समर्थन में विभिन्न आशंकाओं सहित यदि कोई हों तो विस्तृत परिकलन प्रस्तुत करें।	उप श्रमकर अधिक निर्धारित किया जा सकता था तथापि यह परस्पर सहमति से नये कार्गो को आकर्षित करने के लिए 70 रु. प्रति टन की दर से निर्धारित किया गया है। रु. 70/- से अधिक का निर्धारण करने से पड़ोसी पत्तनों की तुलना में अधिक मंहगा होगा और कार्गो दूसरे पत्तनों पर जाने लगेंगे।	
(घ).	पीपीटी, वर्तमान दरमानों में शामिल किए जाने वाली दरोंको लागू करने वाली अभिशासी शर्तों सहित उप श्रम कर का ड्राफ्ट दरमान का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	पीपीटी ने पहले ही दरमानों में सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव पीपीटी को प्रस्तुत कर दिया है जिसमें आईओएचपी पर लौह अयस्क से इतर कार्गो के लिए श्रम उपकर शामिल हैं।  पत्तन ने विविध प्रभार के अंतर्गत सामान्य संशोधन के संबंध में प्रस्तावित ड्राफ्ट दरमानों में निम्न का प्रस्ताव किया है।  *4.9. <u>आईओएचपी में टिप्पलिंगके लिए उप श्रमकर</u> क) लौह अयस्क पल्ले रु. 70 प्रति टन ख) तापीय कोयला रु. 120 प्रति टन"]	
(ङ).	कार्यपरक दिशानिर्देशों के साथ पठित प्रशुल्क नीति 2015 के अनुसार प्रशुल्क नीति कार्यान्वयन के लिए पीपीटी को प्रस्तावित लेवी लगाने के लिए कार्य निष्पादन मानकों का प्रस्ताव करने का अनुरोध किया गया था।	आईओएचपी पर लौह अयस्क पल्लों के प्रस्तावित निष्पादन मानक 15000 मी.टन प्रति दिन है जिनका प्राधिकरण को प्रस्तुत सामान्य दरमानों में पहले से ही उल्लेख किया गया है। पत्तन ने विविध प्रभार के अंतर्गत सामान्य संशोधन के संबंध में प्रस्तावित ड्राफ्ट दरमानों में निम्न प्रस्ताव किया है।	
(च).	प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय पीपीटी ने मै जिंदल स्टील एंड पावर लि. को प्रेषित दिनांक 04 जून 2016 के पत्र की प्रति संलग्न की है जिससे पता चलता है कि पीपीटी ने आईओएचपी के माध्यम से लौह अयस्क पल्लों का प्रहस्तन पहलेही आरंभ कर दिया है तथा रु. 70 प्रति मी. टन का उप श्रमकर पहले ही लागू कर दिया है। तथापि पीपीटीनेइसके लागू करने की प्रस्तावित/वास्तविक अवधि (यदि पहले से ही लागू कर दी है) सूचित नहीं की है।	उप श्रमकर राशि की प्रतिपूर्ति हो जाने तक वसूल की जाती रहेगी। जैसा कि ऊपर बिंदु (क) में उल्लेख किया गया है।	

6. संदर्भगत मामले में एक संयुक्त बैठक 27 सितंबर 2016 को पीपीटी के परिसर में अयोजित की गई। संयुक्त बैठक में पीपीटी ने पाँवर प्वायंट प्रस्तुति दी। इस बैठक में पीपीटी तथा संबंधित उपयोक्ता/उपयोक्ता संगठनों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की।

7. पीपीटी के प्रस्ताव के संबंध में रु. 70 प्रति मी. टन की दर से तदर्थ आधार पर लेवी लगाने, कार्यपरक दिशानिर्देशों के खंड 5.7.1 से 5.7.5 में उल्लेख के अनुसार) प्रशुल्क नीति 2015 के कार्यान्वयन के लिए तथा यह मानते हुए कि पीपीटी ने पहले आईओएचपी पर लौह अयस्क पल्लों का प्रहस्तन कार्य प्रारंभ कर दिया है और यह कि प्राधिकरण को यह मामला तय करने में कुछ समय लगेगा प्राधिकरण ने

अपने आदेश टीएएमपी/55/2016-पीपीटी-दिनांक 04 फरवरी 2017 के द्वारा लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) पर लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन के लिए तदर्थ आधार पर रु. 70/- प्रति मीट्रिक टन की दर का अनुमोदन प्रदान कर दिया है बशर्ते यदि प्राधिकरण द्वारा अन्तिम निर्धारित कर तदर्थ आधार पर निर्धारित दर से कम तय किया जाता है। और अन्तिम व तदर्थ आधार पर तय रु. 70/- रु प्रति मी. टन की दर में संबंधित उपयोक्ताओं को यह आदेश भारत के राजपत्र में राजपत्र सं. 31 पर दिनांक 25 जनवरी 2016 का अधिसूचित कर दिया गया है। हमने 06 फरवरी 2017 के अंतर्गत आदेश की एक - एक प्रति पीपीटी तथा उपयोक्ताओं तथा उपयोक्ता संगठनों को भेज दी है।

8. इस मामले से संबंधित परार्थ कार्रवाई का विवरण प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध है। प्राप्त अभ्युक्तियों तथा उन पर चर्चा से संबंधित उद्धरण संबंधित पक्षों को पृथक-पृथक भेज दिए जाएंगे। ये विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट [Error! Hyperlink reference not valid.](#) पर भी उपलब्ध रहेंगे।

9. इस मामले पर कार्रवाई के दौरान प्राप्त समग्र सूचना और जानकारी के आधार पर निम्न स्थिति उजागर होती है:

(i). पीपीटी के पास कोयला प्रहस्तन के लिए यंत्रीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र है। सीएफएंड एच कामगार कोयला कार्गो की उत्तरायी रेलवे वैगनों से स्वयं करते हैं। एमसीएचपी तक पहुंचाते हैं तथा पोतीय लदानकों के माध्यम से कार्गो का लदान कार्य करते हैं। लौह अयस्क लदान के लिए सुविधा अर्थात् लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) है।

(ii). आईओएचपी को लौह अयस्क प्रहस्तन कार्य के अनुरूप बनाया गया है। वर्ष 2013 से लौह अयस्क प्रहस्तन पर बैन के कारण आईओएचपी का प्रयोग करने के लिए पत्तन ने टिप्पलरों के माध्यम से रेलवे वैगनों से तापीय कोयला का ढुलाई का कार्य शुरू कर दिया जो पहले कामगारों द्वारा की जाती है। तथापि सफाई, प्रेषण और प्रहस्तन (सीएफएंडएच) कामगारों के भारी विरोध के कारण टिप्पलरों के माध्यम से तापीय कोयले की ढुलाई वर्ष 2014 में बंद कर दी गई। अतः आईओएचपी पर कोई कार्य नहीं हो रहा था इसलिए पीपीटी ने सीएफएंड एच कामगारों के लिए विशेष स्वीयरेंस पैकेज (एसएसपी) की अनुमति के लिए एक बारगी मांग का प्रस्ताव सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया है जिसके लिए प्रस्ताव को अनापत्ति प्राप्त हो गई है इस प्रकार पीपीटी ने आरंभ में आईओएचपी के माध्यम से कोयला प्रहस्तन के लिए श्रम उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है।

तथापि, तत्पश्चात्, पीपीटी ने संयंत्र की अतिरिक्त क्षमता को लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन हेतु प्रयोग करने का निर्णय या जो अन्यथा पड़ोसी पत्तनों के माध्यम से प्रहस्तित किए जा रहे थे। इस प्रकार पीपीटी एसएसपी को तापीय कोयला और लौह अयस्क पल्लों को आईओएचपी के माध्यम से प्रहस्तन करने पर उप श्रमकर लगाकर पूरा करने का प्रस्ताव करता है।

आईओएचपी के माध्यम से तापीय कोयला के प्रहस्तन पर उप श्रमकर लगाने का मामला अलग से पारित हो गया है। यह मामला ओएचपी के द्वारा लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन पर उप श्रमकर लगाने के संबंध में है।

(iii). पीपीटी ने अपना प्रस्ताव सितंबर 2016 में प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात्, अनेक स्मरण पत्रों के पश्चात् पीपीटी ने दिसंबर 2016 में सूचना/जानकारी उपलब्ध करायी है। पीपीटी द्वारा प्रस्तुत पीपीटी का कथित प्रस्ताव सूचना एवं जानकारी सहित मामले पर कार्रवाई के दौरान विश्लेषण अनुसार स्वीकार किया जाता है।

(iv). जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है पीपीटी, प्रस्तावानुसार सीएफएंडएच कामगारों के लिए एसएसपी के दायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंधन समिति को प्रदान की गई राशि को वसूल करने में सक्षम है। इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि प्रशुल्क नीति 2015 के अनुसार कर लगाने का उद्देश्य किए गए निवेश के प्रत्यागम और दी गई सेवाओं की लागत को वसूल करने में पत्तन को सक्षम बनाना है। इस संबंध में पीपीटी का विचार है कि प्रबंधन समिति के सीएफएंडएच कामगारों के लिए एसएसपी की समस्त लागत, प्रत्यागम से ब्याज सहित रु. 176/- करोड़ है जो पीपीटी का निवेश है जिसके लिए पत्तन ने आईओएचपी के माध्यम से लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन पर उप-श्रमकर लगाकर पूरा करने का प्रस्ताव किया है।

(v). यद्यपि, लौह अयस्क पल्लों पर उप श्रमकर रु.70/- प्रति मी.टन से अधिक परिकलित होता है, परंतु पत्तन ने इसे 70 रुपये प्रति टन तक ही सीमित रखने का प्रताव किया है। यदि वे पड़ोसी पत्तनों की अपेक्षा पीपीटी पर आईओएचपी के माध्यम से लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन का विकल्प चुनते हैं तो इसके लिए प्रयोक्ता की अतिरिक्त लागत को ध्यान में रखा गया है।

- (vi). इस बात पर विचार करते हुए कि रु.70 प्रति मी.टन की दर उपयोक्ताओं के साथ परामर्श पर आधारित है और न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, प्राधिकरण, आईओएचपी के माध्यम से लौह अयस्क के प्रहस्तन के लिए रु.70/- प्रति मी. टन का उप श्रम-कर की दर के लिए पीपीटी के प्रस्ताव अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है।
- (vii). पूर्वोल्लेखानुसार, पत्तन के अनुरोध के आधार पर यह प्राधिकरण ने 04 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा आईओएचपी पर लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन के लिए रु. 70/- प्रति मी.टन की दर को तादर्थ अनुमोदन प्रदान किया है बशर्ते प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर तदर्थ आधार पर निर्धारित दर अर्थात् 70/- प्रति मी. टन से कम हो तथा तदर्थ व अन्तिम रूप से निर्धारित दर में अंतर के कारण अधिक राशि (अंतर) को संबंधित उपयोक्ताओं को वापस करेगा। यह कि प्राधिकरण और पीपीटी द्वारा प्रस्तावित तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरें बराबर हैं, इस लिए आईओएचपी पर लौह अयस्क पल्लों के लिए रु.70/- की दर को पीपीटी द्वारा लागू करने की तिथि से स्वीकार किया जाता है।
- (viii). पत्तन द्वारा प्रस्तावित कर सीएफएंडएच कामगारों के लिए एसएसपी के विशिष्ट उद्देश्य के लिए रु.176/- करोड़ की भरपाई के लिए प्रस्तावित है। इस संबंध में कर की रु.176 करोड़ की वसूली के लिए समय सीमा निर्धारित करना उपयुक्त होगा। क्योंकि कुल राशि कोयले और लौह अयस्क पल्लों के आई ओएचपी द्वारा प्रहस्तन की मात्रा पर निर्भर करती है इस लिए इस अवस्था में समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। इस लिए पीपीटी को परामर्श दिया जाता है कि इस संबंध में पृथक खाता रखा जाए तथा पीपीटी द्वारा समस्त राशिवसूल हो जाने पर इसे बंद कर दिया जाए। इस संबंध में पीपीटी, आगामी प्रशुल्क समीक्षा के समय प्राधिकरण को एक लेखा परीक्षित रिकार्ड प्रस्तुत करेगा।
- (ix). कार्यपरक दिशानिर्देशों के साथ पठित प्रशुल्क नीति में उल्लेख है कि इसके अनुसार कार्य निष्पादन मानक निर्धारित किए जाएं तदनुसार हमारे अनुरोध पर पीपीटी ने लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन के लिए बर्थ दिवस निष्पादन (औसत) 15000 टन का निष्पादन मानक लक्ष्य रखा है। प्रशुल्क नीति, 2015 में कार्य निष्पादन मानकों के निर्धारण हेतु कोई पद्धति का निर्धारित नहीं किया गया है। पत्तन द्वारा प्रस्तावित मानक यथा प्रस्ताव अनुमोदित किए जाते हैं।

8.1. उपर दिए गए कारणों और समग्र सोच विचार के बाद यह प्राधिकरण आईओएचपी लौह अयस्क पल्लों के प्रहस्तन के लिए रु 70/- प्रति मी.टन के कर तथा पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित औसत पोतीय दिवस निष्पादन के लिए लौह अयस्क पल्लों के 15000 टन के प्रहस्तन संबंधी निष्पादन मानक का अनुमोदन करता है।

8.2. यह लेवी, पीपीटी द्वारा लेवी आरंभ करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी तथा दरों की वैधता पीपीटी के दरमानों में सामान्य संशोधन के लिए अनुमोदित दरों के साथ तालमेल के साथ निर्धारित मान्य होगी।

8.3. इसके पश्चात यह अनुमोदन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, बशर्ते प्राधिकरण द्वारा विशेष कारणों से इसे बढ़ाया न जाए। लौह आयस्क पल्लों के प्रहस्तन हेतु आईओएचपी पर अब अनुमोदित रु. 70/- प्रति मी. टन के कर की पीपीटी के प्रशुल्क की अगली सामान्य समीक्षा के समय समीक्षा की जाएगी। पत्तन से परामर्श दिया जाता है कि वह इस संबंध में पृथक लेखा-जोखा तथा पीपीटी को प्रशुल्क की अगली समीक्षा के दौरान जांच के लिए लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करें।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III/4/असा./472/16]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 23<sup>rd</sup> February, 2017

**No. TAMP/55/2016-PPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Paradip Port Trust for introduction of Labour Cess for Iron Ore Pellets for handling at Iron Ore Handling Plant, as in the Order appended hereto.



**Tariff Authority for Major Ports**  
**Case No. TAMP/55/2016-PPT**

Paradip Port Trust

...  
**QUORUM**

Applicant

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)  
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 8<sup>th</sup> day of February, 2017)

This case relates to a proposal received from the Paradip Port Trust (PPT) for introduction of Labour Cess for Iron Ore Pellets for handling at Iron Ore Handling Plant (IOHP).

2.1. The existing Scale of rates (SOR) of PPT approved in March 2011 prescribes the rates for handling of Iron Ore through IOHP at SI. No (5) of section 2.1 of the existing Scale of Rates of PPT as given below:

SI No.	Description of goods		Rate per MT or part thereof `	
			Foreign	Coastal
5.	(a)	Iron Ore (through IOHP)		
		(i) Shipment upto 1.0 MTPA	23.45	23.45
		(ii) Shipment between 1.0 MTPA and 1.5 MTPA	20.05	20.05
		(iii) Shipment above 1.5 MTPA	16.65	16.65
	(b)	Tippling charges	20.40	20.40
	(c)	Iron Ore (Manual)	23.45	23.45

2.2. However, the existing SOR of PPT does not prescribe rates for handling of Iron Ore pellets through IOHP. Hence, the PPT has come up with the proposal in reference.

3.1. The main points made by the PPT in its proposal dated 8 September 2016 are summarised below:

- (i). The Iron Ore Berth (IOB) with 2 tipplers attached to the berth is the oldest berth of PPT which was commissioned in 1966 primarily for mechanized tippling of Iron Ore from wagons and loading of Iron Ore mechanically by the ship loader at the berth. Over the years, this mechanical system at the berth has been modernized with further capital infusion from time to time.
- (ii). During 2012-13 due to various policies of the Central and State Government, the shipment of Iron Ore cargo stopped, which got coupled with slowing down demand from China. The PPT utilized this facility for tippling of Thermal Coal from BOXN (Open-top wagon) wagons for mechanized loading of Thermal Coal of TANGEDCO & NTECL through IOHP.
- (iii). The average engagement of Clearing, Forwarding & Handling (CF&H) workers who were engaged for unloading of BOXN Thermal Coal rakes, was drastically reduced. This Thermal Coal Cargo was shifted to Mechanised Coal Handling Plant (MCHP) storage area and was mechanically loaded to ship. Consequently, from 14 November 2014 the tippler at IOHP had remained idle, primarily to ease the problem created by CF&H workers under the Management Committee.
- (iv). It was considered by the PPT Board of Trustees (as per the decision of the CF&H Workers Management Committee) to extend the financial grant by PPT to fund the Voluntary Retirement Scheme (VRS) of CF&H workers with the clearance of MOS for ending with CF&H workers problem/industrial dispute, which will pave the way for resumption of mechanized handling of Thermal Coal through IOHP tippler. The BCG, the consultant appointed by MOS (through IPA), had earlier advised the PPT to explore this benefit that would create additional handling of 3.5 lakh MT of Thermal Coal for export from IOHP as the same would be beneficial to Thermal Coal exporters apart from influencing the other efficiency parameters of PPT.
- (v). Based on recommendation of Trustees Sub-Committee constituted by PPT Board, the Central Govt.

clearance was sought on the following issues:

- (a). To allow PPT for funding of ₹. 49 Cores, as a grant to the Management Committee for allowing VRS of 320 workers. The proposed grant may be realized by handling 2 rakes manually and 2 rakes mechanically through tippler per day. The amount of ₹. 49 Cores incurred to fund the VRS will be recouped within two years.
  - (b). To allow PPT for comprehensive VRS for balance 740 workers after they opted for the same, by keeping the VRS open for next 12 months for which the total amount of ₹. 127 Cores as grant may be provided by PPT. The above amount can be recouped by switching over to complete mechanized unloading of 4 BOXN Thermal Coal rakes in a day, so that the amount of ₹. 127 cores grant can be recouped in another two and half years.
  - (c). It was considered and agreed that, though the prevailing situation in PPT and Govt. policy do not permit any regulation, however, the entire facts and events explained in foregoing chapter may be placed before the MOS for taking sympathetic view considering the long association of balance CF&H workers for their multi decades of contribution for the growth of the port.
  - (d). In view of the request received from the workers as well as the Unions of CF&H workers, MOS was requested to examine the issue sympathetically about workers regularization issue and issue appropriate orders so that the industrial peace and harmony at PPT is not disturbed.
- (vi). The MOS, Govt. of India vide letter no. LB-1601/5/2013-DO(L), dated 22 March 2016 gave its “No Objection” to PPT to extend grant to Management Committee for funding Special Severance Package (SSP) (which was termed as VRS) by the Management Committee. MOS also advised PPT that it should ensure recouping the grant so extended by imposing “Labour Cess” on Thermal Coal to be handled through IOHP.

(A copy of the letter in reference from MOS No. LB-1601/5/2013-DO (L) dated 22 March 2016 has been furnished by the PPT alongwith its proposal dated 24 May 2016 for levy of Labour Cess for Handling of Thermal coal via IOHP.)

- (vii). The PPT has already extended ₹. 77,81,19,663/- as grant to Management Committee as follows:

Sr. No.	Date of Grant	No of CF&H workers under SSP	Amount of grant extended by PPT (in ₹.)
1	05.05.2016	283	43,64,03,213/-
2	31.05.2016	188	34,17,16,450/-
	<b>Total</b>	471	77,81,19,663/-

Further, the SSP for CF&H workers as per earlier decisions is open for one year w.e.f. 22.03.2016 to 21.03.2017 and as per clearance of MOS, PPT will extend further amount of ₹. 98,18,80,337/- as grant (out of total approx. grant of ₹. 176 Crores) for funding the SSP of balance CF&H workers.

- (viii). The total amount of expenditure can be recouped by PPT by imposing “Labour Cess” which was proposed as ₹.130/- per ton. The same has been finally agreed mutually to ₹.120/- per ton by PPT, TANGEDCO and NTECL and same was approved by TAMP vide its Order no. TAMP/31/2016-PPT dated 21 June 2016 on adhoc basis for Thermal Coal.
- (ix). Subsequently, the PPT realized that the spare capacity of the plant can be utilized for handling of Iron Ore Pellets which was moving through neighboring private port, primarily with a view to realize the potential for generation of about 3.5 lakh tonnes of cargo per month for the idle IOHP system. The parties of PPT are willing to handle Iron Ore Pellets in the similar way of thermal coal (Mechanical handling via Tippler).
- (x). It is understood that, such Iron Ore Pellets can immediately move to PPT, if the Labour cess to be levied is comparatively less than the Labour cess considered on Thermal Coal to make the total expenditure for shipment of Iron Ore Pellets through IOHP competitive to the total cost incurred at the neighboring private port.
- (xi). An analysis done in the matter envisages that Iron Ore Pellets can give an optimal ship day productivity of about 25,000 MTs in comparison of ship day productivity of 14,913 MTs in case of Thermal Coal

through IOHP achieved in 2014-15.

- (xii). Therefore, considering the ship day productivity of Iron Ore Pellets and even if PPT railway distance is approx. 30 kms more than the private port, the shipper is likely to bear additional cost of approx. ₹. 59/- per tonne in railway freight plus Labour cess if charged ₹. 120/- per tonne. Therefore, it was considered to charge ₹. 70/- as Labour cess on Iron Ore Pellets through IOHP also.
- (xiii). Commensurate with this development, PPT saw opportunities of handling Iron Ore for Coastal/ Foreign export as the Central Government took decisions to rationalize the Custom Duty on Iron Ore fines coupled with decision of the Railway Board to remove the "Duel Freight Structure" for Iron Ore movement by wagons which was earlier being charged for domestic and export purpose. This has resulted in resumption in movement of Iron Ore for mechanized tipping through IOHP. However, no Labour Cess has been considered for imposing on Iron Ore fines, as IOHP is primarily designed for handling Iron Ore and the approved SOR of PPT by TAMP not considered any levy of Labour Cess.
- (xiv). The proposed levy of labour cess of ₹. 70/- per MT towards handling of Iron Ore Pellets has the approval of Board of Trustees of PPT.
- (The PPT has furnished copy of the Proceedings of the Board Meeting, which reflects the approval of the Board of Trustees for the proposed levy of ₹. 70/- per MT towards handling of Iron Ore Pellets at IOHP.)
- (xv). One of the user organisations M/s Jindal Steel & Power has agreed to pay additional Cess of ₹. 70/- per MT for their cargo being mechanically handled from tipping to vessel loading with regard to Iron ore pellets, in addition to the current statutory port charges with regard to mechanical handling of iron ore pellets.

(A copy of the letter of M/s Jindal Steel & Power is furnished by PPT.)

3.2. In this backdrop, the PPT has requested this Authority to approve the proposed labour cess of ₹. 70/- per MT for handling of Iron Ore Pellets on adhoc basis, as has been done in case of Labour Cess for Handling of Thermal Coal.

4. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the PPT proposal dated 8 September 2016 was forwarded to the concerned users/ user organisations vide our letter dated 16 September 2016 seeking their comments. None of the users/ user organisations have furnished their comments till the case was taken up for finalization.

5. While acknowledging the proposal, the PPT was requested vide our letter dated 16 September 2016 to furnish Annexures forming part of the Agenda note placed by the PPT before its Board of Trustees. The PPT was also requested to furnish additional information/ clarification on few points. After reminders dated 17 October 2016 and 16 November 2016, the PPT under cover of its e-mail dated 26 December 2016 has responded. The information/ clarification sought by us and the response of PPT thereon are tabulated below:

Sl. No.	Information/ clarification sought by TAMP	Response of PPT				
(a).	The PPT in its proposal dated 8 September 2016, has requested the Authority to approve the recovery of Labour Cess @ ₹. 70/- per MT, on Ad-hoc basis, for Handling of Iron Ore Pellets through Iron Ore Handling Plant (IOHP) to enable to recover the amount paid to Management Committee to meet the liability of Voluntary Retirement Scheme (VRS) for Clearing, Forwarding & Handling (CF&H) workers. In this regard, it is relevant to mention here that as per the Tariff Policy, 2015, the purpose of any levy is to enable the port to recover the cost of rendering the services and a component of return on the investments. In this backdrop, the PPT to formulate the proposal of seeking approval for Labour Cess to recover the cost of rendering the service to handle Iron Ore Pellets through Iron Ore	<p>As per the approval of Govt. of India, PPT has to bear the cost of SSP for CF&amp;H workers of Management Committee which stands at ₹. 176 crores. This amount may be treated as investment of PPT which is to be recovered through the proposed labour cess including interest. Considering the present trend of traffic during last 7 months (May 2016 to Nov 2016) 1.5 million MT of cargo i.e. thermal coal and Iron Ore Pellet will be handled in IOHP. Accordingly, a calculation of recovery of investment along with interest for next 3 years considering ₹. 110 per tonne as labour cess is given below. The labour cess will continue to be charged till the total amount of investment and interest on investment is recovered.</p> <p>1<sup>st</sup> Year</p> <table><tr><th>Particulars</th><th>Amount in ₹.</th></tr><tr><td>Cost of investment (SSP)</td><td>176,00,00,000</td></tr></table>	Particulars	Amount in ₹.	Cost of investment (SSP)	176,00,00,000
Particulars	Amount in ₹.					
Cost of investment (SSP)	176,00,00,000					

	Handling Plant (IOHP) and the Return on the related investment.	Interest (8%)	14,08,00,000
			190,08,00,000
		Labour Cess per tonne	110
		Quantity per annum (considering actual of 8.5 lakh tonnes handled for 7 months)	15,00,000
		Amount to be recovered annually	16,50,00,000
		Indirect net revenue generation on account of tippling, IOHP charges, terminal charges, haulage charges @ ₹.100/- per tonne.	15,00,00,000
			31,50,00,000
		Carry forward to next year	158,58,00,000
		2 <sup>nd</sup> Year	
		<b>Particulars</b>	<b>Amount in ₹.</b>
		Cost of investment (SSP)	158,58,00,000
		Interest (8%)	12,68,64,000
			171,26,64,000
		Labour Cess per tonne	110
		Quantity per annum (considering actual of 8.5 lakh tonnes handled for 7 months)	15,00,000
		Amount to be recovered annually	16,50,00,000
		Indirect net revenue generation on account of tippling, IOHP charges, terminal charges, haulage charges @ ₹100/- per tonne.	15,00,00,000
			31,50,00,000
		Carry forward to next year	139,76,64,000
		3 <sup>rd</sup> Year	
		<b>Particulars</b>	<b>Amount in ₹.</b>
		Cost of investment (SSP)	139,76,64,000
		Interest (8%)	11,18,13,120
			150,94,77,120
		Labour Cess per tonne	110
		Quantity per annum (considering actual of 8.5 lakh tonnes handled for 7 months)	15,00,000
		Amount to be recovered annually	16,50,00,000
		Indirect net revenue generation on account of tippling, IOHP charges, terminal charges, haulage charges @ ₹. 100/- per tonne.	15,00,00,000
			31,50,00,000
		Carry forward to next year	119,44,77,120
(b).	The PPT to indicate the annual volume of Iron Ore Pellets estimated to be handled via IOHP.	Already clarified at point (a) above.	
(c).	The PPT is reported to have arrived at the rate of proposed Labour Cess for Iron Ore pellets at ₹.70/- per MT by considering a ship day	The labour cess should have been fixed beyond ₹. 70/- per tonne. However, it was agreed mutually to fix at ₹. 70/- per tonne to attract new cargo. Anything beyond ₹. 70/-	

	productivity of Iron Ore Pellets at about 25000 MTs and the fact that PPT railway distance is approx. 30 kms more than private port. In this connection, the PPT to furnish a detailed working in support of ₹.70/- per MT alongwith the basis for the various assumptions, if any, relied upon.	will be costlier as compared to neighboring ports and cargo may be diverted.
(d).	The PPT to propose the draft SOR of Labour Cess along with conditionalities to govern the application of rates to be incorporated in its existing SOR.	PPT has already submitted its proposal to TAMP for revision of General SOR which includes labour cess for cargo to be handled at IOHP other than iron ore. [The Port is seen to have proposed the following in the proposed draft Scale of Rates relating to general revision proposal under 'Miscellaneous charges' -  <b>"4.9. <u>Labour cess for tipping in IOHP.</u></b> a) Iron ore pellet ₹. 70 per tonne b) Thermal coal ₹.120 per tonne"]
(e).	As per Tariff Policy, 2015, read alongwith the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Policy, the PPT was requested to propose Performance Standards for the proposed levy.	The proposed performance standard of IOHP for handling Iron Ore Pellet is 15,000 MT per day which is already indicated in the General SOR submitted to TAMP. [The Port is seen to have proposed average berth day output of 15000 tonnes for iron ore pellets in IOHP in its General revision proposal.]
(f).	While filing the proposal, the PPT has furnished a copy of letter sent to M/s Jindal Steel & Power Limited dated 04 June 2016, which indicates that, the PPT has already started handling of Iron ore pellets through IOHP and has implemented the proposed Labour Cess at ₹.70/- per MT. However, the PPT has not indicated proposed / actual period (if already implemented) for which the proposed Labour Cess would be applicable.	The labour cess will continue to be charged till the amount is received as is already indicated at point (a) above.

6. A joint hearing on the case in reference was held on 27 September 2016 at the PPT premises. At the joint hearing, the PPT made a brief power point presentation of its proposal. The PPT and the concerned users/ user organizations have made their submissions at the joint hearing.

7. With regard to the proposal of the PPT seeking approval for levy of the rate of ₹.70 per tonne on ad hoc basis, based on the stipulation contained in Clauses 5.7.1 to 5.7.5 of the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Policy, 2015, and considering that PPT has already commenced handling of iron ore pellets at IOHP and that it may take some time for the case to mature for final disposal by this Authority, this Authority vide its Order No. TAMP/55/2016-PPT dated 04 January 2017 has granted ad hoc approval for introduction of Labour Cess at PPT at the rate of ₹. 70/- per MT for the Iron Ore pellets handled at Iron Ore Handling Plant (IOHP), subject to the condition that if the final rate fixed by the Authority is lower than the adhoc rate of ₹.70/- per MT, the difference between the final rate and the adhoc rate has to be refunded by the PPT to the concerned users. The Order has been notified in the Gazette of India on 25 January 2016 vide Gazette No. 31. We have vide our letter dated 6 February 2017 forwarded a copy of the Order to PPT and to the relevant users / user organizations.

8. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

9. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i). The PPT has a Mechanized Coal Handling Plant for shipment of coal. The Clearing, Forwarding & Handling (CF&H) workers unload coal cargo manually from the Railway wagons, transport the cargo to the MCHP and load the cargo on board the ship through ship loaders. There is a separate facility to handle iron ore i.e. Iron Ore Handling Plant (IOHP).
- (ii). The IOHP has been designed to handle Iron ore. In view of ban on handling of Iron Ore since 2013 and to make use of the IOHP, the port started unloading thermal coal from Railway Wagon through tipplers, which was earlier handled manually. However, due to strong resistance from the CF&H

workers, unloading thermal coal through tippers was discontinued in the year 2014. Given that the IOHP was virtually idle, PPT has reported to have referred the matter to the Government for approval of one-time grant to meet the financial requirement for allowing Special Severance Package (SSP) for CF&H workers, who in turn has given 'No Objection' to the proposal. Thus, the PPT initially furnished a proposal for levy of labour Cess on thermal coal handled through IOHP.

However, subsequently, the PPT decided to utilize the spare capacity of the plant by handling Iron Ore Pellets, which was otherwise moving through neighboring private port. Thus, the PPT proposes to recoup the SSP through a levy of labour Cess on thermal coal and iron ore pellets as well handled through IOHP.

The Order fixing labour Cess on thermal coal handled through IOHP has been passed separately. This case is with regard to fixation of labour Cess on iron ore pellets handled through IOHP.

- (iii). The PPT had filed its proposal in September 2016. Subsequently, after several reminders, the PPT has furnished information/ clarification in December 2016. The said proposal of PPT alongwith the information/ clarification furnished by PPT during the processing of the case in reference is considered in this analysis.
- (iv). As brought out above, the proposal of the PPT is to enable it to recover the amount paid to Management Committee to meet the liability of SSP for CF&H workers. In this regard, it is relevant to mention here that as per the Tariff Policy, 2015, the purpose of a levy is to enable the port to recover the cost of rendering the services and a component of return on the investments. In this connection, the PPT is of the view that the overall cost of SSP for CF&H worker of Management Committee at ₹ 176 crores alongwith with interest in the form of return, is the investment of PPT, which the port proposes to recover by way of levy of labour cess on iron ore pellets handled through IOHP.
- (v). Though the labour cess on iron ore pellets works out to be more than ₹ 70/- per MT, it has chosen to restrict the levy to ₹ 70/- per MT, taking into account the additional cost that the users may have to bear, if they choose to handle iron ore pellets through IOHP at PPT rather than at any other neighbouring port.
- (vi). Considering that the rate of ₹ 70/- per MT is based on the consultation with the users and has the approval of the Board of Trustees, this Authority is inclined to approve the rate of ₹ 70/- per MT towards labour cess on iron ore pellets handled through IOHP, as proposed by the PPT.
- (vii). As stated earlier, based on the request made by the port, this Authority vide its Order dated 4 January 2017 has granted ad hoc approval for introduction of Labour Cess at PPT at the rate of ₹ 70/- per MT for the iron ore pellets handled at Iron Ore Handling Plant (IOHP), subject to the condition that if the final rate fixed by this Authority is lower than the adhoc rate of ₹ 70/- per MT, the difference between the final rate and the adhoc rate has to be refunded by the PPT to the concerned users. Given that the rate levied by the PPT on adhoc basis and the final rate approved by this Authority are the same, the levy of ₹ 70/- per MT towards handling of iron ore pellets at IOHP with effect from the date of commencement of the levy by PPT is recognized as such.
- (viii). The proposed levy is to enable the port to recoup the amount of ₹ 176 Crores for the specific purpose of SSP for the CF&H workers. In this connection, it may be appropriate to fix a time frame for levy of the amount of ₹ 176 Crores. Since the recovery of the entire amount depends on the coal and iron ore pellets handled and to be handled at IOHP, it is not possible to fix the time frame at this stage. Therefore, the PPT is advised to maintain a separate account in this regard and stop the levy once the entire amount is recovered by the PPT. An audited account in this regard is to be produced by the PPT to this Authority, at the time of next review of tariff of PPT.
- (ix). The Tariff Policy, 2015 read with the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Policy stipulates prescription of Performance Standards. Accordingly, at our request, the PPT has proposed to prescribe the Performance standard as Average Ship Berth day Output in respect of handling of Iron ore pellet at 15,000 tonnes. The Tariff Policy, 2015, does not prescribe any method or basis for proposing performance standards. The performance standard as proposed by the Port is approved.

8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, this Authority approves the levy of ₹ 70/- per MT towards handling of iron ore pellets at IOHP and the Performance standard as Average Ship Berth day Output in respect of handling of Iron ore pellet at 15,000 tonnes, as proposed by the Port.

8.2. The levy would come into effect from the date of commencement of the levy by PPT and the validity of the rate would be co-terminus to the validity of the rates to be approved in the general revision of Scale of Rates of PPT.

8.3. The approval accorded would automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority. The levy of ₹ 70/- per MT towards handling of iron ore pellets at IOHP approved now shall be reviewed at the time of next general review of tariff of PPT. The port is advised to maintain a separate account in this regard and furnish the audited details for scrutiny at the time of the next review of tariff of PPT.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)  
[ADVT.-III/4/Exty./472/16]